भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1988

29 अगस्त, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण पुनर्गठन पैकेज

1988. श्री ईश्वर सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में वस्त्र उद्योग के लिए ऋण पुनर्गठन पैकेज को मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के स्वामित्व वाली वस्त्र मिलों, विशेषकर उन मिलों का जो पिछले कुछ वर्षों से बंद पड़ी हैं, का पुनर्गठन किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार के ऋण पुनर्गठन पैकेज के द्वारा वस्त्र उद्योग को मदद पहुंचाने की इस पहल से ऐसी मिलों में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में किस हद तक सहायता मिलेगी?

उत्तर

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी)

(क) से (ङ.): वस्त्र मंत्री ने वस्त्र उद्योग के ऋण पुनर्गठन के लिए वित्त मंत्री को पत्र लिखा है । वस्त्र उद्योग पर दबाव की सीमा के बारे में बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्किट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन ने वस्त्र उद्योग को 155,809 करोड़ रु. का कुल निधि आधारित ऋण अभिज्ञात किया है और 35,000 करोड़ रु. के **संकटकालिक** ऋण की मात्रा का अनुमान लगाया है । बैंक ऑफ बड़ौदा की सिफारिशें वित्त मंत्री द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं । भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:-

(i) द्वितीय पुनर्गठन पर परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ का मामला औचित्यपूर्ण नहीं है ।

(ii) प्रावधानीकरण पर मांगी गई रियायत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्याशित हानियों के लिए प्रावधानीकरण प्रथम सुरक्षा है ।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक ने मूल धनराशि के पुर्नभुगतान पर ऋण स्थगन और कार्यशील पूंजी को 3-5 वर्षों की अवधि में भुगतान योग्य कार्यशील पूंजी आवधिक ऋणों में परिवर्तित करने के संबंध में 'अनापत्ति' व्यक्त की है ।

ऋण पुनर्गठन पैकेज में निजी क्षेत्र के लगभग 307 वस्त्र मिलें और एसएमई क्षेत्र के लगभग 200 आरएमजी कारखाने शामिल हैं । ऋण पुनगर्ठन के कार्य से देश में वस्त्र उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी ।